इस्मा ने कहा, शुगर का एक्स-मिल MSP ₹36 करे सरकार

[जयश्री भोसले | पुणे]

शुगर इंडस्ट्री ने चीनी की एक्स-मिल मिनिमम सेलिंग प्राइस (एमएसपी) में 24 पर्सेंट बढ़ोतरी करके इसे 29 से 36 रुपये करने को कहा है। मिलों का कहना है कि ऐसा होने पर वे सरकार से वित्तीय मदद के बिना एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगी। इंडस्ट्री ने सरकार से यह भी मांग की है कि 20 पर्सेंट चीनी का एक्सपोर्ट करना अनिवार्य बनाया जाए। 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे पेराई सीजन 2018-19 में यह 70 लाख टन रह सकता है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इंडस्ट्री से 15 दिनों में इन दोनों मांगों को मानने की अपील की है। इस्मा के डायरेक्टर जनरल अबिनाश वर्मा ने ईटी से कहा, 'इंटरनेशनल ट्रेड हाउसों एल्वीन, कॉफको, सकडेन ने सूचना दी है कि अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच भारतीय चीनी की विदेश में मांग निकल सकती है। उस समय ब्राजील और थाईलैंड जैसे चीनी के बड़े निर्यातक बाजार में नहीं होंगे। इसलिए अगले 15 दिनों में 60-70 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के प्रोग्राम का ऐलान किया जाए।'

उन्होंने कहा, 'हमने केंद्र सरकार को पत्र सौंपकर शुगर का एक्स-मिल मिनिमम प्राइस (एमएसपी)

- इंडस्ट्री ने यह भी कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे पेराई सीजन 2018-19 में 20% शुगर का एक्सपोर्ट अनिवार्य किया जाए

₹36 प्रति किलो करने का अनुरोध किया है, जिससे हमारी प्रॉडक्शन कॉस्ट कवर हो जाएगी। हमने 2018-19 सीजन में सभी मिलों के लिए प्रॉडक्शन का 20 पर्सेंट हिस्सा एक्सपोर्ट के लिए अनिवार्य करने की मांग भी की है।'

एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि अगर तय कोटे का निर्यात ना हो तो सरकार उसे जब्त करके अपनी एजेंसियों के जरिये निर्यात करे। इंडस्ट्री बॉडी अब एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स को एसोसिएट मेंबर का दर्जा दे रही है। एसोसिएशन का दावा है कि एमएसपी को ₹36 प्रति किलो करने से इंडस्ट्री को ज्यादातर समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा।

इस्मा ने कहा, 'इसका यह फायदा होगा कि इंडस्ट्री को सरकार की वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही सेस कलेक्शन की जरूरत होगी। सरकार को मंथली रिलीज कोटा भी तय नहीं करना होगा और ना ही गन्ने का कोई बकाया होगा।' उसने कहा है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है।

E.T. (Hindi)
10-8-2018